

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 16/07/2025

विषय:- बिहार राज्य में अगले 5 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) के लिए कुल राशि रु० 300 करोड़ (तीन सौ करोड़ रुपये) के अनुमानित लागत के साथ "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु० 20,98,00,000/- (रुपये बीस करोड़ अन्धानवे लाख) मात्र व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य में अगले 5 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) के लिए कुल राशि रु० 300 करोड़ (

(ii) राज्य की जनता के लिए 24x7 आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श प्राप्त करने की स्वचालित तकनीक के माध्यम से व्यवस्था करना।

(iii) राज्य की जनता के स्वास्थ्य का अनुश्रवण एवं उसमें सहयोग प्रदान करना।

(iv) मरीजों के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/उच्च चिकित्सीय सुविधा केन्द्रों पर रेफर करने एवं उनके आवागमन की निर्बाध सुविधा प्रदान करने में डिजिटल तकनीक का प्रयोग करना।

(v) मरीजों के चिकित्सीय जॉच एवं परामर्श को डिजिटल तकनीक के माध्यम से संधारित करना, ताकि किसी भी चिकित्सीय संस्थान में उन्हें जॉच रिपोर्ट का कागज ले जाने की आवश्यकता नहीं हो।

5- राज्य की जनता को उपर्युक्त लाभ प्रदान किए जाने के साथ ही इस योजना से राज्य के स्वास्थ्य सुविधा की प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी काफी सहायता मिलेगी। इस क्रम में इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित कार्य आसान हो जायेंगे :-

(i) पेशेवर चिकित्सीय व्यवस्था एवं सहायता की उपलब्धता एवं उनका अनुश्रवण आसानी से हो सकेगा।

(ii) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली का एकरूप मानक तैयार करने में आसानी होगी।

(iii) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में संलग्न कर्मियों/संस्थानों/उपकरणों की कार्यक्षमता एवं

8- इस योजना के अन्तर्गत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, निम्न रूप में होगा :-

- (i) भारत सरकार के द्वारा स्थापित मानकों (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) के अनुरूप होगा।
- (ii) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सभी key components के साथ एक-दूसरे के अनुकूल (Compatible) होगा।
- (iii) इस योजना में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ कोई दोहराव नहीं है अपितु यह दोनों एक दूसरे के अनुपूरक होंगे।
- (iv) स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जितने भी आवश्यक App हैं उनको यथावत या Upgrade करके इसके साथ संबद्ध किया जाएगा।
- (v) इस व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुपस्थिति विवरणी को वेतन भुगतान से संबंधित App/Platform के साथ संबद्ध किया जाएगा। साथ ही चिकित्सकों की अनुपस्थिति की समस्या के निराकरण में भी मदद मिलेगी।

9- इस योजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाना है, जिसके तहत प्रथम वर्ष में इसके Design Development के साथ 3(तीन) जिलों में Pilot Basis पर Go Live किया जाएगा। इसके पश्चात् दूसरे वर्ष में इसे शेष 35 (पैंतीस) जिलों में Roll Out किया जाएगा।

10- इस योजना के Design Development में प्रथम वर्ष (2022-23) में ₹0100 करोड़ (एक सौ करोड़ रुपये) द्वितीय वर्ष (2023-24) में लगभग रुपये 80 (अस्सी) करोड़ तथा शेष तीन वर्षों (2024-25, 2025-26 एवं 2026-27) में Operation एवं Maintenance के लिए प्रति वर्ष 40 करोड़ की दर से कुल 120 (एक सौ बीस करोड़ रुपये) अर्थात् कुल 300 करोड़ रुपये (तीन सौ) की लागत आकलित किया गया है।

15- राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना इस राशि का धन ऋणज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) एवं व्यय के सुसंगत भावचर्स/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे।

16- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक-27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

17- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

18- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-07/विविध-28-56/2021-22 के पृष्ठ-...../टि० में प्राप्त है।

19- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

20- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

21- यह मात्र व्ययादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से